भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1122

08 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: उत्तराखंड में सहकारी ढाँचे को सुदृढ़ करना

1122 # श्री नरेश बंसल :

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार उत्तराखंड में सहकारी ढाँचे को सुदृढ़ करने का कोई विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख)क्या उत्तराखंड में सरकारी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए धनराशि आवंटित की गई है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित साह)

(क) और (ख): देश में पहले से ही एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है । देश में सहकारी क्षेत्र के दो प्रकार के ढांचे हैं - राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां। बहु-राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सहकारी समितियां राज्य सरकार के अधीन आती हैं, जिनमें उत्तराखंड राज्य में कार्यरत सहकारी समितियां भी शामिल हैं । सरकार अपने दो प्रमुख संस्थानों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से पहले से ही उत्तराखंड राज्य में कई सहकारी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रही है। एनसीडीसी ने कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत योजना (सीएसआईएसी) के तहत उत्तराखंड में सहकारी समितियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है:

वर्ष	दी गई सहायता (लाख रुपये में)		
	लोन	सब्सीडी	कुल
2018-19	10523.21	83.32	10606.53
2019-20	430.99	802.91	1233.90
2020-21	10.25	1712.10	1722.35

इसी प्रकार, एनसीसीटी ने में अपने सहकारी प्रबंधन संस्थान, देहरादून के माध्यम से राज्य में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागी	महिला सहभागी
2018-19	78	2255	473
2019-20	70	2107	561
2020-21	55	1403	333

*****